

रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण पूरा हुआ- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए

जयपुर, 1 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को शीघ्र अंतिम रूप देने और इसके लिए केन्द्र

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना के अंतर्गत बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बरौटा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ़ (जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिये।

परियोजना (संशोधित पाबंती-कालीसिंह-चम्बल लिंक परियोजना) के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने परियोजना के पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए, शेष कार्यों को निश्चित समयबद्धि में पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए। साथ ही, परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बरौटा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ़

(जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। शर्मा ने परियोजना के विभिन्न घटकों के अलाइनमेंट की जानकारी भी ली और परियोजना से संबंधित समस्त कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के काफ़र डेम एवं डेनेज

फीडर का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य, मेज एनीकट से गलवा बांध के डूब क्षेत्र तक फीडर ड्रेन, गलवा बांध से ईसरदा डूब क्षेत्र और बीसलपुर डूब क्षेत्र फीडर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।

इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

निशिकांत दुबे ने बिना शर्त माफी मांगी

नई दिल्ली/मुंबनेश्वर, 01 अप्रैल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को नेहरू-गांधी परिवार के बारे में अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया और अगर किसी को भावनाएं आहत हुई हों तो मैं बिना शर्त माफी चाहता हूँ।

यह विवाद निशिकांत दुबे की 27 मार्च की टिप्पणी से उभरा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी घन और सीआईए एजेंटों के सहयोग

■ **बीजू पटनायक पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी और माफी मांगी।**

से युद्ध लड़ा था, तथा ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच कड़ी का काम किया था।

इस दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के अग्रणी नेताओं में शुमार बीजू पटनायक के संदर्भ में बोली गई मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया।

यह मेरा व्यक्तिगत बयान है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू पटनायक के ऊपर समझा गया।

निशिकांत दुबे ने कहा बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के नेता रहे हैं और रहेंगे।

मेरे वक्तव्य से अगर किसी को भावनाएं आहत हुई हों तो मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूँ।

‘उपासना सैन्ट्रिक’ बिल्डिंग के निर्माण में भारी लापरवाही, बिल्डर से जवाब तलब

हाईकोर्ट ने इस बिल्डिंग के निर्माण से परेशान अधिवक्ता हेमंग कुमावत द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे के आदेश दिये

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 1 अप्रैल। बिल्डरों द्वारा रिहायशी इलाकों में ऊंची इमारतें बनाते समय आसपास पड़ोस में रह रहे निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिस तरह अनदेखी की जाती है वह वर्तमान में गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए अधिवक्ता हेमंग कुमावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल हेमंग टॉक रोड पर गांधी नगर मोड़ पर ए-1 कृष्णा नगर के निवासी हैं और उन्हीं के घर से संलग्न उपासना बिल्डर द्वारा “उपासना सैन्ट्रिक” नामक मल्टी स्टोरी का निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि जैसे-जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे-वैसे ही उनके मकान में बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन का मलबा गिरने लगा। उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेडीए को कठोर आदेश दिये हैं कि 2 अप्रैल गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वे किया जाये और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च रिपोर्ट अगले 2-3 दिनों में ही अदालत में पेश की जाये।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने कई बार बिल्डर व कॉन्ट्रक्टर से संपर्क करा ताकि किसी दिन गंभीर मामला ना हो जाये। परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने याचिका में बताया कि 18 फरवरी 2026 को एक बिल्डिंग की छत से भारी भरकम मलबा उनके मकान पर गिरा जिससे कार में नुकसान हुआ और घर की खिड़कियां भी टूट गईं।

■ अधिवक्ता हेमंग कुमावत ने याचिका में बताया कि बिल्डिंग निर्माण के दौरान उसके घर पर मलबा गिर रहा है, जिससे उसके घर को नुकसान हुआ है।

■ अदालत ने जेडीए को भी फटकारा क्योंकि उसके आदेश के बावजूद उक्त क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिल्डर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कदम उठाये गये।

■ अदालत ने अगले 2-3 दिनों में ही सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये।

उन्होंने इस वारदात को शिकायत और उनके घर में हुई क्षति के बारे में ज्योति नगर थाना में सूचना दी और जेडीए में भी इसकी शिकायत दर्ज की थी। जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए बिल्डर ने अपनी भूल मानी और क्षमा भी मांगी। परंतु इसके बावजूद बिना किसी सुरक्षा के बिल्डिंग का कार्य निरंतर चलता जा रहा है और आये दिन अधिवक्ता हेमंग कुमावत के मकान पर मलबा गिर रहा है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मोघा ने 16 मार्च को जेडीए व उपासना ग्रुप और ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन को भी नोटिस जारी करे थे। और कहा था कि कन्स्ट्रक्शन कंपनियों बिना सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण कार्य कर रही हैं जिससे याचिकाकर्ता के मकान को नुकसान हो रहा है। उन्होंने जेडीए को आदेश दिये थे कि वह मौका मुआयना करे और यह सुनिश्चित करे कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को जायेगी निर्माण

कंपनियों द्वारा। न्यायाधीश गणेश मोघा ने सर्वे की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। हैरानी की बात है कि जेडीए ने कोर्ट के आदेश अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने जेडीए के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वे किया जाये और उसकी रिपोर्ट अगले 2-3 दिनों में ही अदालत में पेश की जाये।

अमरावती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बिल में उन किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय होनी चाहिए थी, जिन्होंने अमरावती को रासधानी बनाने के लिए अपनी ज़मीनों दी थी।

प.बंगाल, तमिलनाडु, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस और माकपा झूठे, मनगढ़त और भ्रामक दावे कर रहे हैं। ये संशोधन किसी धर्म या संगठन के खिलाफ नहीं है। चुनावों को देखते हुए विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है।

इस समय चल रहे खाड़ी संघर्ष और आगामी राज्य चुनावों के अभियान के बीच, सरकार ने 25 मार्च को चुपचाप एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के तहत, केन्द्र सरकार को हजारों संगठनों की विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों, जैसे स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थल, पर व्यापक अधिकार मिल जाते। खासकर केरल में विपक्षी दलों ने इसका कुछ विरोध किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। वाम दलों और कांग्रेस दलों ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक संगठनों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया

है। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि यह कानून आरएसएस को लाभ पहुंचाएगा। राज्य सरकारें भी चिंतित हैं, क्योंकि यदि यह कानून लागू होता है तो एफसीआरए से जुड़ी सभी जांचों पर केन्द्र को वीटो पावर मिल जाएगी, जिससे राज्यों की भूमिका पूरी तरह दरकिनारा हो जाएगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि यह विधेयक पारित हुआ, तो केन्द्र गैर-भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्तियां जब्त कर सकता है। गौतमलब है कि इन संशोधनों में स्वतंत्र अपीलीय निकाय का भी प्रावधान नहीं है, और सभी फैसले कार्यपालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी के हाथ में होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित बदलाव “डेजिगनेटड अथॉरिटी” का गठन है, जिसे किसी संगठन का पंजीकरण रह होने, समर्पित (सरेन्डर) होने या समाप्त होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नियंत्रण लेने का अधिकार होगा।

सहायक निदेशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सचिव नरेश गोकलानी ने सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) विकास जैफ को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

इस नोटिस में विकास जैफ से तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि, क्या बायोफ्यूल प्राधिकरण में पदस्थापन के लिए विकास जैफ ने कोई आवेदन किया था?

यदि आवेदन किया था तो कब और किस माध्यम से अथवा सीधे ही बायोफ्यूल प्राधिकरण में आवेदन किया था? क्या उन्होंने आवेदन से पूर्व कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग से इस संबंध में प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की थी?

इन तीनों बिंदुओं पर विकास जैफ को 7 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं, इसके बाद ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में निर्णय होगा।

बुरी तरह निराश, “घायल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था। टूटने में गलती से वेनेजुएला को बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल मान लिया था।

दूसरी ओर, ईरान भी उतना ही मुखर है कि वह युद्धब्राम नहीं करेगा और लड़ाई जारी रखेगा। ईरान यह भी कह रहा है कि उसके नेता सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

यदि कुछ हुआ, तो ईरान को उसकी मौजूदा स्थिति में छोड़ देना सबसे खराब परिणाम होगा। पूरा पश्चिम एशिया, यानी सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और अन्य सभी, ईरान के रहस्यो-करम पर होंगे। युद्ध के दौरान वे पहले ही आतंकित हो चुके हैं, और अधिक शक्तिशाली हुआ ईरान उन्हें और भ्रमित करेगा।

एकमात्र पक्ष, जो न तो जीत का दावा कर रहा है और न युद्ध के अंत की बात कर रहा है, वह इजरायल है, जिसने ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले किए हैं और लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान चले किया है। यदि अमेरिका अचानक इस पूरे मामले से हाथ खींच लेता है, तो इजरायल असुरक्षित हो जाएगा।

इजरायल की अजेय होने की छवि बुरी तरह टूट चुकी है। उसे न तो ईरान पर और न हिज्बुल्लाह पर ही कोई स्पष्ट जीत मिली है। बल्कि, हिज्बुल्लाह और अधिक आक्रामक हो सकता है।

इसलिए, युद्ध के परस्पर विरोधी दावे दुनिया को वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ वह पहले थी, बल्कि शायद उससे भी बदतर स्थिति में। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह उधराव और अव्यवस्था की स्थिति है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दुनिया भर के देश तेल और गैस की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय कर रहे हैं। इसका आर्थिक प्रभाव कम विकसित और गरीब देशों पर और भी गंभीर होगा। अफ्रीकी देश पहले से ही इसके प्रभाव की शिकायत कर रहे हैं।

लेकिन सबसे बड़ा नुकसान संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उसकी छवि को धक्का लगा है। अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार ने कहीं और नहीं, बल्कि वहीं शासन परिवर्तन की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के लिए यह कितनी शर्मनाक वापसी है।

चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय पर बम धमाका

खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की जिम्मेवारी ली

चंडीगढ़, 01 अप्रैल। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बुधवार की शाम हुए बम धमाके की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी आतंकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एनआईए तथा सेना के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस 37 स्थित भाजपा कार्यालय की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा यूटी चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली तथा हरियाणा के पंचकुला की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

बुधवार की शाम पांच बजे के करीब सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कारण पार्किंग में खड़े कई वाहन तथा इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस को कई टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंची। इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से एक वीडियो मिला है। जिसमें एक युवक ग्रेनेड का पिन निकालकर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह पंजाबी में गालियां देते हुए भाग जाता है। हमलावरों की संख्या दो होने की

■ **पुलिस को घटना का एक सीसी टीवी फुटेज मिला है जिसमें एक युवक ग्रेनेड से पिन निकालते हुए और ग्रेनेड फेंक कर भागते हुए दिख रहा है।**

आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच अभी चल रही ही रही थी कि खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सैल, सीएफएसएल की टीमों तथा एनआईए की टीमों ने मामले को जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, सेना के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं।

चाहते हैं कि उसके पास पंजाब के सिख युवाओं को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।

इस बीच चंडीगढ़ की एसएसपी कंवर्दार पुर को ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सैल, सीएफएसएल की टीमों तथा एनआईए की टीमों ने मामले को जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, सेना के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं।

छह वर्ष की बालिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह किराए के मकान में रहकर रेस्तरां में काम करता है, जहां अभियुक्त भी उसके साथ काम करता है। सुबह वह अपने दोनों बच्चों को लेकर रेस्तरां पर काम करने आया था। दोपहर के समय अभियुक्त उसकी साढ़े छह साल की बेटी को उसके किराए के मकान की ओर ले गया था। जब काफी देर तक बेटी नहीं लौटी, तो उसने उसे आसपास तलाशा,

लेकिन उसका पता नहीं चला। इस पर उसने अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने बच्चों से दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखकर छत पर छोड़ आया। उस उसने छत पर जाकर देखा कि रिपोर्ट में उसकी बेटी की लाश मिली। कोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक

कुवैत सिटी, 01 अप्रैल। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बुधवार को बताया कि कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। इससे फ्यूल स्टोरेज टैंकों में भीषण आग लग गई। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

गल्फ न्यूज के दुबई कार्यालय से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार, सिविल एविएशन अथॉरिटी के आधिकारिक प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजदी ने कहा कि यह हमला ईरान और उसके समर्थक सशस्त्र समूहों ने किया। उन्होंने इसे हवाई अड्डे पर “खुला हमला” बताया। उन्होंने बताया कि ड्रोन ने कुवैत एविएशन फ्यूल कंपनी के फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया। इससे उस जगह पर भीषण आग लगी। हालात को नियंत्रण में करने के लिए तुरंत आपातकाल बलों को भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि नुकसान सिर्फ सामान का ही हुआ है।

लिएंडर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की। खेल और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुक्त सारणीय है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिएंडर पेस ने भी ‘एक्स’ पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति उनके जुनून से अभिभूत हूँ। आभिकों की मांग कि हिस्सा बनकर और आपके मार्गदर्शन में देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जय हिंद, जय भारत।